कानपुर, बुधवार, 13 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 118, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

# स्वराज इंडिया

इनसाइड यूपी में डिजिटल क्रांति...>Pg12

बुलडोजर एक्शन से कांपे प्लाटिंग माफिया...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

# ब्राह्मण पर टिप्पणी से बवाल

# सपा की चुप्पी पर उठे सवाल

## सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान पर मचा घमासान, कांग्रेस भी हुई हमलावर

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की ब्राह्मण समाज को लेकर की गई विवादित टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। 'ब्राह्मणों से अच्छी तो वेश्याएं होती हैं' जैसे आपत्तिजनक बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे 'सपा की असली मानसिकता' बताया है, वहीं सहयोगी दल कांग्रेस ने भी खुलकर असहमति जताते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस बयान को पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को जातीय घृणा फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन किसी समाज के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। अजय राय ने सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मांग की कि केवल औपचारिक माफी नहीं, बल्कि संबंधित नेता पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

उधर, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बार-बार समाज को जातियों में बांटने और सामाजिक समरसता को तोड़ने की राजनीति करती रही है। पाठक ने आरोप लगाया कि सनातन और हिंदू समाज के प्रति अपमानजनक सोच अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह केवल एक नेता की व्यक्तिगत सोच है या फिर पार्टी की अंदरूनी विचारधारा का हिस्सा।

भाजपा नेताओं ने इसे 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि सपा सत्ता के लिए जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि इस विवाद से सपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है।

सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पूरे विवाद के बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। विपक्षी दलों ने इसे 'मौन समर्थन' बताते हुए हमला तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि पार्टी नेतृत्व वास्तव में इस बयान से असहमत है तो तत्काल कार्रवाई और सार्वजनिक माफी सामने आनी चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर भाजपा और सपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखे होने की संभावना जताई जा रही है।

### भाजपा को कैसे मिला बड़ा मुद्दा?

भाजपा लंबे समय से सपा पर "जातीय राजनीति" और "हिंदू विरोधी मानसिकता" के आरोप लगाती रही है। अब इस विवाद ने भाजपा को सीधे हमला बोलने का मौका दे दिया है। पार्टी इसे सामाजिक सम्मान और सनातन अस्मिता से जोड़कर व्यापक राजनीतिक अभियान का रूप दे सकती है।

### ब्रजेश पाठक का पलटवार

ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह बयान समाजवादी पार्टी की विभाजनकारी सोच को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा लगातार सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों पर हमला करती रही है तथा यह विवाद उसी मानसिकता की एक और मिसाल है।

### अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठे सवाल

अखिलेश यादव की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आने से विपक्ष हमलावर हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे "रणनीतिक चुप्पी" बताया है, जबकि कांग्रेस के भीतर भी इस पर असहजता महसूस की जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सपा नेतृत्व की देरी पार्टी को और नुकसान पहुंचा सकती है।

### चुनावी असर कितना गहरा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में विवादित बयान विपक्षी गठबंधन की सामाजिक इंजीनियरिंग को प्रभावित कर सकता है। यदि मामला लंबा खिंचता है तो यह 2027 चुनाव तक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रह सकता है।

### सपा के लिए क्यों बढ़ा संकट?

राजकुमार भाटी का बयान ऐसे समय आया है जब समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जातीय वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी से पार्टी की "समाजवादी और सर्वसमावेशी" छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। भाजपा इसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।

### कांग्रेस की नाराजगी क्यों अहम?

इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस का खुलकर विरोध दर्ज कराना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संदेश गया कि सहयोगी दल भी इस बयान से असहज हैं। कांग्रेस का दबाव बढ़ने पर सपा नेतृत्व को सफाई या कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

### अजय राय ने क्या कहा?

अजय राय ने कहा कि किसी भी समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने सपा नेतृत्व से मांग की कि केवल बयान जारी कर मामले को दबाने की कोशिश न हो, बल्कि संबंधित नेता के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए।

# कानपुर सेंट्रल पर फिर बढ़ा अवैध पानी का कारोबार, यात्रियों से वसूले जा रहे मनमाने दाम

## गर्मी बढ़ते ही स्टेशन परिसर में सक्रिय हुए गैर-अधिकृत वेंडर, रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर। भीषण गर्मी के बीच कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और उसके आसपास अवैध वेंडरों की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और बाहरी क्षेत्रों में गैर-अधिकृत पानी की बोतलों की खुलेआम बिक्री की जा रही है। आरोप है कि यात्रियों को बिना मानक और बिना लाइसेंस वाले पानी को निर्धारित कीमत से अधिक दामों पर बेचा जा रहा है।यात्रियों का कहना है कि कई वेंडर रेलवे की अधिकृत सूची में शामिल नहीं हैं, फिर भी वे बेखौफ होकर प्लेटफॉर्मों और स्टेशन के बाहर पानी बेच रहे हैं। इन बोतलों पर न तो गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है और न ही रेलवे की स्वीकृति से जुड़ी जानकारी। इसके बावजूद गर्मी और प्यास से परेशान यात्री मजबूरी में महंगे दाम देकर पानी खरीदने को विवश हैं।**

स्थानीय लोगों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्टेशन परिसर में नियमित जांच और निगरानी नहीं होने के कारण अवैध कारोबारियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कई यात्रियों ने शिकायत की कि 20 रुपये की बोतल 30 से 40 रुपये तक में बेची जा रही है।यात्रियों का यह भी आरोप है कि अवैध वेंडरों के कारण अधिकृत विक्रेताओं का कारोबार प्रभावित हो रहा है और स्टेशन पर अव्यवस्था का माहौल बन रहा है। लोगों ने मांग की है कि रेलवे प्रशासन तत्काल अभियान चलाकर ऐसे वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और केवल अधिकृत दुकानों से ही पानी की बिक्री सुनिश्चित कराए। गर्मी के मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में रेलवे की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को सुरक्षित, शुद्ध और निर्धारित कीमत पर पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

खास खबर

### गैर-अधिकृत पानी कितना खतरनाक?

- बिना मानक वाला पानी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
- अशुद्ध पानी से डायरिया, टायफाइड, उल्टी और पेट संबंधी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।
- कई बार दोबारा इस्तेमाल की गई बोतलों में भरा पानी भी बेचा जाता है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं।
- गर्मी में दूषित पानी शरीर में डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार यात्रियों को केवल सीलबंद और अधिकृत ब्रांड का पानी ही खरीदना

# भीषण गर्मी में सेंट्रल पर यात्रियों के लिए रेलवे ने लगाया ठंडे पानी का स्टाल

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ठंडे पानी का स्टाल लगाया गया। बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं से परेशान यात्रियों को निःशुल्क ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया।स्टाल पर यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली। प्यास से बेहाल यात्रियों ने ठंडा पानी पीकर राहत महसूस की। कई यात्री पानी पीने के साथ अपनी बोतलों में भी पानी भरते नजर आए। ठंडा पानी मिलते ही यात्रियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने रेलवे की इस पहल की सराहना की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि सफर के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को गर्मी से काफी राहत मिली।

# चट्टा हटाओ अभियान में 6 गाय पकड़कर भेजीं कांजी हाउस

## स्वरूप नगर क्षेत्र में चला अभियान, विरोध के बीच पुलिस और प्रवर्तन दल ने संभाला मोर्चा

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को स्वरूप नगर क्षेत्र में अवैध चट्टों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 गायों को पकड़कर कांजी हाउस जाजमऊ भेज दिया।

अभियान में क्षेत्रीय थाना स्वरूप नगर एसएचओ, पुलिस बल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. निरंजन, प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण तथा जोनल अधिकारी जोन-4 श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र में चट्टा हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चट्टा संचालक अकबर और उसके परिवार की महिलाओं द्वारा विरोध किया गया, लेकिन पुलिस और प्रवर्तन दल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अभियान जारी रखा। टीम ने चट्टे से 6 गायों को पकड़कर सुरक्षित रूप से कांजी हाउस भेज दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध रूप से संचालित चट्टों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों और अवैध डेयरियों के कारण यातायात बाधित होने के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभियान में राजस्व निरीक्षक अवधेश तिवारी, कमल सिंह, कृष्ण मुरारी, प्रवर्तन दल के टीम लीडर सत्यवीर, महेंद्र नाथ तथा राजस्व निरीक्षक दिनेश कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

# केडीए के बुलडोजर एक्शन से कांपे प्लाटिंग माफिया, बाकी जोन में कार्रवाई पर सवाल!

## जोन-3 में भी 66 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, लेकिन अन्य इलाकों में अब भी धड़ल्ले से कट रहीं कॉलोनियां

**प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया**

**कानपुर।** कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के तेजतर्रार ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह को प्रवर्तन जोन-3 का भी चार्ज दे दिया गया है. बुधवार सुबह चली बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा दिया। विशेष कार्याधिकारी एवं उप जिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में फत्तेपुर क्षेत्र में लगभग 66 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 3 घंटे 45 मिनट तक चली कार्रवाई में 4 जेसीबी मशीनों ने अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नाले, बाउंड्रीवाल, बिजली पोल, सीवर लाइन, एंट्री गेट और निर्माणाधीन भवनों को जमींदोज कर दिया।

केडीए उपाध्यक्ष श्री अंकुर कौषिक और सचिव श्री अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई को हाल के दिनों की सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।

बताया गया कि मनोज सिंह भदौरिया व अन्य द्वारा फत्तेपुर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और बिना प्राधिकरण की अनुमति के बड़े पैमाने पर प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। केडीए की टीम ने पूरे क्षेत्र को ध्वस्त कर साफ संदेश देने की कोशिश की कि अवैध कॉलोनियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

### 6 और अवैध प्लाटिंग चिन्हित, चलेगा बुलडोज़र

केडीए ने प्रवर्तन जोन-3 में 6 अन्य अवैध प्लाटिंग भी चिन्हित की हैं, जिनमें बिनगवां, रमईपुर, बिधनू और सेन पश्चिम पारा, जरौली क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

### जोन-1 और जोन-3 में ही क्यों दिख रहा एक्शन?

केडीए की इस कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शहर के अन्य जोनों में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जबकि जाजमऊ, रामादेवी, एयरपोर्ट के आसपास नौबस्ता, बिधनू, मंधना, चौबेपुर, सचेंडी, पनकी, कल्याणपुर और दक्षिण क्षेत्र सहित तमाम इलाकों में खुलेआम अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।

सूत्रों की मानें तो कई इलाकों में बिना ले-आउट स्वीकृति के खेतों को प्लॉट में बदला जा रहा है और खरीदारों को सपनों के नाम पर फंसाया जा रहा है। इसके बावजूद संबंधित जोनों में प्रवर्तन की कार्रवाई लगभग ठप दिखाई दे रही है।

केडीए में इन दिनों डॉ. रवि प्रताप सिंह की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार बुलडोजर कार्रवाई से जहां प्लाटिंग माफियाओं में खौफ है, वहीं आम लोगों में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि जोन-1बी और जोन-3 में इतनी सख्ती हो सकती है तो बाकी जोनों में आखिर सन्नाटा क्यों पसरा है। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह ने ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश भविष्य में आर्थिक और कानूनी संकट खड़ा कर सकता है।

# कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने किया आरोपी का हाफ एनकाउंटर

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

**कानपुर।** कानपुर के फीलखाना क्षेत्र में होजरी कारोबारी विजय चौरसिया की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गंगा बैराज के पास हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में चली गोली उसके पैर में लगी।घायल अवस्था में उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर का तमंचा बरामद किया है।

पूछताछ में आरोपी विशाल गुप्ता ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि विजय चौरसिया से ब्याज के पैसों को लेकर उसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन वह विजय को प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने सवाई सिंह का हाता स्थित धर्मशाला ले गया। वहां छत पर दोनों के बीच पैसों को लेकर फिर कहासुनी हुई।विशाल के मुताबिक,

**➪ गंगा बैराज के पास पुलिस से हुई मुठभेड़, तमंचा बरामद; मददगारों पर भी कार्रवाई की तैयारी**

विजय ने रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि किसी तरह की लिखापढ़ी नहीं है। इसी बात से गुस्साए विशाल ने पीछे से उसके सिर में गोली मार दी। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज अहम साबित हुए। फुटेज में आरोपी शाम करीब 6:32 बजे विजय को स्कूटी पर बैठाकर धर्मशाला की ओर ले जाता दिखाई दिया, जबकि करीब 7:20 बजे वह अकेले वहां से निकलता नजर आया।इसके बाद फीलखाना पुलिस समेत कई थानों की टीमों ने उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन उन्नाव और कन्नौज में भी मिली।

पुलिस के अनुसार, फरारी के दौरान विशाल ने कई परिचितों के यहां पनाह ली। उसके मददगारों की तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एडीसीपी शिवा सिंह ने बताया कि आरोपी के सहयोगियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।जांच में यह भी सामने आया है कि विशाल लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम करता था।विजय चौरसिया को उसने दोस्ती के चलते कम ब्याज दर पर रकम दी थी, लेकिन बाद में भुगतान को लेकर विवाद बढ़ता गया।

हालांकि, मामले में पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हत्या के बाद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि कारोबारी को पिस्टल से गोली मारी गई थी, जबकि अब बरामद हथियार 32 बोर का तमंचा बताया जा रहा है। पुलिस ने हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

## परमट स्कूल में भूमिपूजन पर सियासी संग्राम

# भाजपा-सपा समर्थकों में बवाल

### विधायक और सांसद निधि के निर्माण कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद सड़क तक पहुंचा

### नारेबाजी-धरना और पुलिस दखल के बाद जांच एडीएम सिटी को सौंपी गई

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर। परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय बुधवार को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। विद्यालय में प्रस्तावित निर्माण कार्य के भूमिपूजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आमने-सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी, हंगामा और धरना शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम ने शहर की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है।**

जानकारी के मुताबिक आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी की विधायक निधि से विद्यालय में तीन कमरों के निर्माण का प्रस्ताव है, जबकि भाजपा सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से स्मार्ट क्लास और बाउंड्रीवाल बनाए जाने हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने निर्माण कार्य का भूमिपूजन पहले कराने को लेकर अड़े हुए थे। इसी खींचतान ने बुधवार को खुला राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लिया।

बताया गया कि सुबह सपा समर्थकों द्वारा विद्यालय परिसर में निर्माण के लिए नींव की खुदाई कराई जा रही थी। इसी दौरान भाजपा नेता सुरेश अवस्थी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। परिसर में जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। आरोप है कि विवाद के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की ओर से सपा विधायक को चप्पल दिखाई गई।

विवाद की सूचना मिलते ही विधायक अमिताभ बाजपेयी भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए धरना शुरू कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में विकास कार्य रोका जा रहा है, जबकि भाजपा समर्थकों का कहना था कि नियमों की अनदेखी कर एकतरफा तरीके से काम शुरू कराया गया।स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए विधायक अमिताभ बाजपेयी को डीसीपी सेंट्रल कार्यालय ले जाया, जिसके बाद सपा के कई नेता और समर्थक वहां भी पहुंच गए। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके।

इस पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विकास कार्य अब जनहित से ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बनते जा रहे हैं।

सरकारी स्कूल, जहां बच्चों की पढ़ाई और सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वहां राजनीतिक दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ खुलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।

## निजीकरण टेंडर के विरोध में उबला नगर निगम

# काला फीता बांध कर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

### किदवई नगर जोन-3 में सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन, 14 मई की आमसभा में बड़े आंदोलन की चेतावनी

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर। नगर निगम में प्रस्तावित निजीकरण टेंडर के विरोध में कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जोन-3 किदवई नगर में सफाई, उद्यान, अभियंत्रण एवं मार्गप्रकाश विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने 14 मई को मोतीझील मुख्यालय पर आयोजित होने वाली आमसभा में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।**

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे जनहित में किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन नगर निगम प्रशासन की मनमानी के चलते उन्हें आंदोलन और कार्यबंदी के लिए मजबूर किया जा रहा है। नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित आउटसोर्स सेवा निगम के शासनादेश तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हुए लगभग 10 वर्षों से कार्यरत करीब 5000 आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को निजी कंपनियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है।

सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर निजीकरण टेंडर निरस्त कराने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि पूर्व की व्यवस्था के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनियों से मानवबल आपूर्ति सुनिश्चित कर सफाई व्यवस्था चलाई जाए।

कर्मचारी नेताओं ने मंडलायुक्त एवं शासन-प्रशासन से पुनः टेंडर स्थगित करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मचारी आंदोलन और कार्यबंदी के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की होगी।

सभा में जयपाल सिंह, हरिओम वाल्मीकि, रमाकांत मिश्र, विनोद रावत, मुन्ना हजारिया, अजीत बाघमार, मुकेश वाल्मीकि, पिंटू चौधरी, धीरज गुप्ता, रमेश चंद शुक्ला, सुधाकर मिश्र, कमरुद्दीन, अखिलेश सिंह, रामगोपाल चौधरी, राकेश परिहार, राजेंद्र वाल्मीकि, बृजलाल भारती और बउआ वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

#### निजीकरण से यों बढ़ा असंतोष?

नगर निगम कर्मचारियों का मानना है कि निजीकरण लागू होने से वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी असुरक्षित हो जाएगी। कर्मचारियों को डर है कि नई निजी कंपनियां पुराने कर्मचारियों को हटाकर कम वेतन पर नए लोगों की भर्ती कर सकती हैं।

#### प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

नगर निगम प्रशासन के लिए यह मामला अब केवल टेंडर प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। हजारों कर्मचारियों की नाराजगी और संभावित आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पर समाधान निकालने का दबाव तेजी से बढ़ रहा है।

#### सफाई व्यवस्था पर या पड़ेगा असर?

यदि कर्मचारी कार्यबंदी पर जाते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
गर्मी और बरसात के मौसम में कूड़ा उठान और नालियों की सफाई
बाधित होने से स्वास्थ्य संबंधी संकट भी पैदा हो सकता है।

#### कल की आमसभा पर टिकी निगाहें

मोतीझील मुख्यालय में गुरुवार को प्रस्तावित आमसभा को कर्मचारियों के आंदोलन का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यदि बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया तो शहर में नगर निगम सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है।

## सम्पादकीय

# नीट परीक्षा रद्द होने से प्रतिभाएं हतास

हमारे तंत्र की नाकामी और परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचारियों की बढ़ती सेंध का ही नतीजा है कि पेपर लीक के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए तीन मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब पौने तेईस लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये परीक्षाएं देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5400 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

दरअसल, पेपर लीक होने के आरोपों के बाद जांच एजेंसियों की सिफारिश पर परीक्षा रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कथित रूप से डेटा लीक और धांधली की व्यापक जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि व्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए फिर से परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

कहा जा रहा है कि एनटीए ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा निष्कर्षों की प्रारंभिक जांच के आधार पर परीक्षा स्थगन का फैसला लिया। निस्संदेह, इस फैसले ने उन लाखों छात्रों को निराश ही किया है जो महीनों से परीक्षा की तैयारी में लगे थे। अब उन्हें नये सिरे से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने एनटीए व केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कहा जा रहा है कि एनटीए में सुधार नहीं, अब पूरी संरचना बदलने की जरूरत है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि एनटीए के बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है। राजनेता पीपर लीक व प्रश्नपत्रों में गलती सामने आने को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने की मांग की जा रही है। साथ ही एनटीए के उद्देश्य और कार्यक्षमता को लेकर शंका जतायी जा रही है।वहीं कांग्रेस का आरोप है कि एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से पांच में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं। इनमें जेईई मेन्स 2025 उत्तर कुंजी के दोषपूर्ण होने पर प्रश्नपत्र में 12 प्रश्न वापस लेने पड़े थे। मांग है कि एनटीए को केंद्रीयकृत करने के बजाय संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। वहीं एनटीए कह रहा है कि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। यह भी कि एनटीए अपने संसाधनों का प्रयोग करके दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी की जवाबदेही स्वीकारी है। दरअसल, आरोप है कि नीट का पेपर 'क्वेश्चन बैंक' के जरिये लीक किया गया, जिसमें फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीन से ज्यादा सवाल थे। जिसमें आधे हूबहू परीक्षा में आए। आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिये ये प्रश्नपत्र लाखों तक पहुंचे। हालांकि, इस मामले का खुलासा सीकर से हुआ, लेकिन कहते हैं कि पेपर पहले केरल से एक मई को आया और उसके तार नासिक से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े थे। एनटीए ने कहा है कि सात मई की रात एक व्हिसलब्लोअर से उन्हें पेपर लीक की सूचना मिली।

# जनता के लिए त्याग : नेताओं के लिए विशेषाधिकार ?

श्याम सिंह पंवार
वरिष्ठ पत्रकार

देशहित के नाम पर समय-समय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, देश की जनता से ऐसी अपील करते हैं जोकि उनके बयानों पर सटीक न दिखकर उनकी ही कार्यशैली से विरोधाभास को हवा देते दिखते हैं।

अभी हाल ही के भाषण की बात करें तो वे (मोदी) 'राष्ट्रहित' में लोगों से अपनी आदतें बदलने का संदेश देते हैं जैसे- पेट्रोल - डीजल, कम खर्च करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएँ और कहते दिखते हैं कि, 'एक वर्ष तक सोना न खरीदें', तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर हर बार बलिदान केवल आम जनता ही क्यों दे ?

सोना न खरीदने के पहलू पर बात करें तो सोना, केवल शौक नहीं, भारत की सामाजिक और आर्थिक परम्परा का हिस्सा है। लाखों कारीगर, सुनार, छोटे व्यापारी और उनके परिवार इसी उद्योग पर पूरी तरह से निर्भर हैं। यदि जनता एक साल तक सोना खरीदना बन्द कर देगी तो सबसे पहले चोट बड़े उद्योगपतियों पर नहीं, बल्कि उन गरीब कारीगरों पर पड़ेगी जिनकी रोज़ी-रोटी पहले से ही महँगाई और बेरोज़गारी की मार झेल रही है। क्या एनडीए सरकार के पास उनके लिए कोई ठोस योजना है ? या फिर यह भी 'आत्मनिर्भरता' व 'देशभक्ति' के नाम पर जनता के सिर मढ़ दिया जाएगा?विडम्बना देखिए, देश की जनता से कहा जाता है कि पेट्रोल बचाइए, लेकिन नेताओं के दर्जनों गाड़ियों वाले काफिले सड़कों पर शान से दौड़ते हैं, जैसा कि नजारे दिख रहे हैं। आम आदमी को मितव्ययिता का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि सत्ता के गलियारों में फिजूलखर्ची खुलेआम दिखाई देती है। यदि वास्तव में देशहित सर्वोपरि है, तो शुरुआत सत्ता के शीर्ष से क्यों नहीं होती? सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित, क्या मंत्रियों और नेताओं के काफिलों में कटौती होगी? क्या सरकारी ऐशो-आराम पर रोक लगेगी ? क्या जनता को भी वही अनुशासन दिखेगा जो उनसे अपेक्षित है ? देशभक्ति का अर्थ यह नहीं कि जनता हर स्तर से आर्थिक बोझ चुपचाप उठाती रहे और सत्ता केवल उपदेश देती रहे। असली नेतृत्व वह होता है जो उदाहरण पेश करे, न कि केवल भाषण, जैसाकि नरेन्द्र मोदी के बयानों में साफ दिखता है। उनके अधिकतर बयानों में 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे...' वाली कहावत पर सटीक बैठते है। वहीं यदि एनडीए सरकार जनता से त्याग मांगती है, तो उसे पहले अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना होगा। आज देश की परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रसीले भाषणों से ज्यादा ईमानदार नीतियों को अपनाने की जरूरत है। देश की जनता अब केवल अपील नहीं, बल्कि समानता और जवाबदेही चाहती है, क्योंकि, लोकतंत्र में राष्ट्रहित का बोझ केवल नागरिकों के कन्धों पर नहीं, सत्ता के कन्धों पर भी बराबर का होना चाहिए। जिसका अभाव, एनडीए की मोदी सरकार में साफ देखा जा सकता है।

# नीट परीक्षा रद्द, सिस्टम पर उठते सवाल?

**सवाल यह है कि आखिर बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा माफिया की साजिशें कब थमेगी? यह कोई नई घटना नहीं। पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं।**

संजय सक्सेना,लखनऊ,
वरिष्ठ पत्रकार

तीन मई को संपन्न हुई नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। देशभर के लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। नीट परीक्षा में करीब 24 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। पेपर लीक की खबरों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। राजस्थान से पेपर आउट होने की अफवाहें तेज हैं और विपक्ष ने इसे मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। छात्र सड़कों पर उतर आए, आक्रोश की लहर दौड़ गई। सरकार ने आनन-फानन में नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा माफिया की साजिशें कब थमेगी? यह कोई नई घटना नहीं। पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया, बल्कि राजनीतिक घमासान भी खड़ा कर दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार की बातें बेईमानी साबित हो रही हैं? क्या सरकार भरोसा दिला सकती है कि दोबारा परीक्षा लीक नहीं होगी? बात नीट कांड की शुरुआत कैसे हुई, की जाए तो तीन मई को सुबह नौ बजे शुरू हुई परीक्षा के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर के सवाल वायरल हो गए। राजस्थान के सीकर और जयपुर इलाकों से लीक की पुष्टि हुई। तत्पश्चात, पुलिस अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें परीक्षा केंद्र के कुछ कर्मचारी और दलाल शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां साजिश के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही हैं। छात्रों का कहना है कि बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पेपर पहले से बिक रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्दीकरण का फैसला लेते हुए नई तारीख जल्द घोषित करने का वादा किया है, लेकिन छात्रों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, मुंबई और पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार वाले चिंतित हैं कि दोबारा परीक्षा का बोझ कैसे झेलें।

पिछले सालों के काले अध्याय याद आते हैं, जब परीक्षा प्रणाली पर सेंध लग चुकी थी। 2015 में वाइब्रेंट गुजरात के दौरान आयोजित जीएलओई परीक्षा का पेपर लीक हुआ। सैकड़ों उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा। फिर 2021 में बिहार के बीपीएससी परीक्षा का मामला सामने आया, जहां पेपर सॉल्वर गिरोह ने हल्ला बोल दिया। 2022 में यूपीटीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन दोषियों को सजा मिलने में देरी हुई। इसी साल फरवरी में रोहिणी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। बिहार में नीट पीजी का कांड तो सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर परीक्षा स्थगित की। महाराष्ट्र में एमपीएससी का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। ये घटनाएं बताती हैं कि शिक्षा माफिया का जाल कितना गहरा है। ये गिरोह परीक्षा केंद्रों के अंदरूनी लोगों से सेटिंग कर पेपर हासिल कर लेते हैं और अमीर छात्रों को बेच देते हैं। इन पेपर लीक मामलों पर राजनीति का खेल हमेशा चरम पर रहता है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर हमला बोलता है। इस बार नीट रद्दीकरण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने संसद में बहस की मांग की। आप के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छात्रों का साथ देते हुए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा ने इसे राज्य सरकारों की साजिश बताया, खासकर राजस्थान और बिहार में। 2022 के यूपीटीईटी कांड में सपा ने योगी सरकार को घेरा था, जबकि भाजपा ने विपक्षी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में नीट पीजी लीक पर आरजेडी और जदयू ने नीतीश कुमार सरकार पर तीर चलाए। हर बार चुनावी मौसम में ये मामले राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। पार्टियां वोट बैंक के लिए छात्र आंदोलनों का फायदा उठाती हैं, लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं देता। यह राजनीतिक नौटंकी छात्रों के दर्द को और बढ़ा देती है।

वैसे, पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लंबा है, लेकिन नाकाफी। पुलिस अक्सर गिरफ्तारियां तो करती है, मगर सजा मिलना मुश्किल होता है। 2022 के यूपीटीईटी मामले में एसटीएफ ने 15 लोगों को पकड़ा, लेकिन अदालत में केस लंबा खिंच गया। बिहार में 2024 के बीपीएससी कांड में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, कई को जमानत मिल गई। राजस्थान पुलिस ने नीट मामले में अब तक आठ को हिरासत में लिया, लेकिन मास्टरमाइंड फरार हैं। कानून में सख्त प्रावधान हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक पर दस साल की सजा और जुर्माना है। फिर भी अमल कमजोर है। सॉल्वर गिरोहों पर नकेल कसने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। कई मामलों में अधिकारी ही शामिल पाए गए, जिससे जांच प्रभावित होती है। कार्रवाई दिखावटी रह जाती है। परीक्षा लीक मामले में न्यायपालिका ने कई बार सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी लीक पर केंद्र को फटकार लगाई और निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। यूपीटीईटी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता। 2023 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक पारदर्शिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सर्विलांस और सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए। लेकिन कोर्ट के फैसले लागू करने में देरी होती है। न्यायपालिका ने कई बार सरकार को केंद्रीय एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, ताकि राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार रोका जा सके। कोर्ट छात्रों के हित में खड़ा दिखता है, लेकिन सिस्टम की कमजोरी उजागर करता रहता है।

एनजीओ ने भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। राइट टू एजुकेशन फोरम और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे संगठन ने कई पिटीशन दाखिल कीं। 2022 में यूपीटीईटी पीड़ित छात्रों ने एनजीओ की मदद से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सोसाइटी ने नीट कांड पर रिपोर्ट जारी कर मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। ये संगठन छात्रों को कानूनी सहायता देते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। बिहार में जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स एनजीओ ने सॉल्वर गिरोह के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किए। एनजीओ ने सरकार पर दबाव डाला कि पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम अपनाया जाए। इनकी सक्रियता से कई मामलों में तेज कार्रवाई हुई, लेकिन संसाधनों की कमी से प्रभाव सीमित रहता है। फिर भी ये सिविल सोसाइटी की आवाज बनते हैं। बहरहाल, लाख टके का सवाल यही है कि यह सिलसिला कब थमेगा? नीट रद्दीकरण ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों का एक साल बर्बाद हो गया। शिक्षा माफिया को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। राजनीतिक दलों को आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सुधार पर ध्यान देना चाहिए। न्यायपालिका और एनजीओ की भूमिका सराहनीय है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर अब भी सुधार नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। छात्रों की मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस कांड से सबक लिया जाएगा।

# फर्जी रजिस्ट्री मामले में कब चलेगा कानून का डंडा?

## अब एफआईआर और गिरफ्तारी पर टिकी हैं सबकी निगाहें

अरुण कश्यप/स्वराज इंडिया

**कानपुर।** बिल्हौर तहसील के बकोठी गांव में सामने आए चर्चित फर्जी रजिस्ट्री कांड में कोर्ट द्वारा आदेश निरस्त किए जाने के बाद अब पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्व अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराने वालों पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई है।

जांच में यह तथ्य सामने आ चुका है कि जिन खातेदारों के नाम पर जमीन बेचे जाने का दावा किया गया, वे पिछले करीब चार से पांच दशक से गांव में रह ही नहीं रहे थे। इसके बावजूद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो गई और खतौनी में नाम भी दर्ज हो गया। अब इसी बिंदु को लेकर पूरे मामले में मिलीभगत और दस्तावेजी फर्जीवाड़े की चर्चा तेज हो गई है। नायब तहसीलदार बिल्हौर कोर्ट द्वारा पूर्व आदेश निरस्त किए जाने और मूल खातेदारों का नाम बहाल करने के निर्देश के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर जब फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है तो दोषियों पर मुकदमा कब दर्ज होगा। मामले में लेखपाल जांच आख्या, तामीला रिपोर्ट और राजस्व विभाग की जांच के आधार पर न्यायालय ने माना कि कथित विक्रेता लंबे समय से गांव में मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद उनकी ओर से बैनामा होना कई स्तरों पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को लेकर हो रही है। लोगों का कहना है कि जब रजिस्ट्री में पहचान और अंगूठे का सत्यापन अनिवार्य है, तो फिर कथित विक्रेताओं की मौजूदगी कैसे दर्ज हो गई। इससे रजिस्ट्री व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

लोगों का मानना है कि केवल खतौनी में नाम बहाल कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि पूरे मामले में आपराधिक जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी इस तरह के फर्जी बैनामों को बढ़ावा मिल सकता है।

फिलहाल राजस्व रिकॉर्ड सुधार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरे मामले में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों पर आखिर कब कानून का डंडा चलेगा, या कानून ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं।




### क्या था पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक कानपुर नगर की बिल्हौर तहसील के बकोठी गांव निवासी कल्याण दत्त और नारायण दत्त पुत्र ओमकार नाथ वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई में बस गए थे। आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भतीजे ने गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनकी जमीन का बैनामा करा दिया। मामले में रोहित की पत्नी श्रीमती कामिनी का नाम खतौनी में दर्ज करा लिया गया था। बाद में शिकायत और जांच के बाद लेखपाल रिपोर्ट, तामीला आख्या और राजस्व जांच में यह तथ्य सामने आया कि कथित विक्रेता दशकों से गांव में मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद नायब तहसीलदार कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 का एक पक्षीय आदेश निरस्त करते हुए श्रीमती कामिनी पत्नी रोहित का नाम खतौनी से हटाने और मूल खातेदार कल्याण दत्त व नारायण दत्त का नाम पुनः बहाल करने के निर्देश दिए।

- बिल्हौर के बकोटी गांव में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री कराए जाने में आरोपियों पर नहीं हो रही कार्रवाई
- तहसील के अधिकारियों ने जाँच में फर्जीवाड़ा पाकर निरस्त किया आदेश
- राजस्व रिकॉर्ड में सुधार शुरू, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वाले अब भी कार्रवाई से कोसों दूर


स्वराज इंडिया

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

मुंबई में रह रहे कल्याण दत्त-नारायण दत्त के नाम पर खेला गया फर्जीवाड़ा उजागर

बिल्हौर: फर्जी रजिस्ट्री में बड़ी कार्रवाई

तहसील से एकपक्षीय आदेश निरस्त

कामिनी पत्नी रोहित का नाम खतौनी से हटाने के आदेश जारी

स्वराज इंडिया खबर का असर

स्वराज इंडिया के खुलासे के बाद जांच में सामने आई सच्चाई

स्वराज इंडिया

बड़ा भू-घोटाला बेनकाब

मुंबई में बैठे चाचा की जमीन बिल्हौर में भतीजे ने बेच दी

नायब तहसीलदार कोर्ट का आदेश

राजस्व सुधार शुरू, लेकिन कार्रवाई पर सस्पेंस

फर्जीवाड़े से अनजान बने बैठे हैं बिल्हौर तहसील के रजिस्ट्रार

प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल बायोमेट्रिक सत्यापन भी संदेह के घेरे में




### ऐसे केस में कई जा चुके जेल लेकिन बकोठी कांड में नहीं हुई कार्रवाई

प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्री और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के कई मामलों में पुलिस फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेज चुकी है। कानपुर समेत कई जिलों में फर्जी बैनामा, फर्जी पहचान और मृतक या गैर हाजिर खातेदारों के नाम पर जमीन बेचने वाले गिरोहों पर मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारी भी हुई।ऐसे मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और सरकारी अभिलेखों में फर्जीवाड़े जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन बकोठी फर्जी रजिस्ट्री कांड में कोर्ट द्वारा आदेश निरस्त किए जाने और जांच में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलने के बावजूद अब तक किसी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है।

## दिन दहाड़े सूने घर में चोरी, शिक्षिका के मकान से नकदी-जेवर पार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चौबेपुर कस्बे में मंगलवार को चोरों ने दिनदहाड़े एक शिक्षिका के बंद पड़े घर को निशाना बनाकर हजारों की नकदी और जेवरात पार कर दिए। वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस व्यवस्था के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली। चौबेपुर के ब्रह्मनगर मोहल्ला निवासी शालिनी सिंह एक कॉलेज में शिक्षिका हैं। मंगलवार सुबह वह रोजाना की तरह स्कूल चली गई थीं। घर पर उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद नहीं थीं और पति अश्वनी सिंह अपनी बीमार मां को इलाज के लिए कानपुर ले गए थे। इसी दौरान सूना मकान देखकर चोरों ने घर में धावा बोल दिया।दोपहर में घर पहुंचीं शालिनी सिंह ने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कमरों का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। चोरों ने अलमारी और लॉकर तोड़कर उसमें रखी नकदी व जेवरात समेट लिए थे। सूचना मिलते ही चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक घर से करीब छह हजार रुपये नकद के अलावा सोने-चांदी के जेवर चोरी हुए हैं।

## मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट से किशोरी की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**कानपुर।** चौबेपुर थाना क्षेत्र के इंदलपुर जुगराज गांव में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। मोबाइल फोन चार्जिंग के दौरान करंट लगने से 17 वर्षीय किशोरी अंशिका की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में शोक का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक गांव निवासी रामचंद्र की बेटी अंशिका बुधवार सुबह करीब चार बजे उठी थी। बताया जा रहा है कि वह अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाने के लिए स्विच बोर्ड के पास गई। इसी दौरान अचानक उसे तेज करंट का झटका लगा और वह मौके पर ही अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे से आवाज आने पर परिजन दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिवार के लोग तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौबेपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सूचना पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने घर में लगे बिजली उपकरणों और चार्जिंग पॉइंट की जांच की। शुरुआती जांच में मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट उतरने की आशंका जताई गई है। थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने से मौत का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

### मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां

- कभी भी गीले हाथों से मोबाइल चार्जर न लगाएं।
- खराब, कटे या लोकल चार्जर का इस्तेमाल करने से बचें।
- चार्जिंग के दौरान मोबाइल का अत्यधिक उपयोग न करें।
- खुले तार या ढीले स्विच बोर्ड तुरंत बदलवाएं।
- बिजली के उपकरणों को बच्चों और नमी वाली जगहों से दूर रखें।
- रातभर मोबाइल चार्जिंग पर छोड़ने से बचें।
- स्पार्किंग या झटका महसूस होने पर तुरंत मेन स्विच बंद करें।

# मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन, परिवार में पसरा मातम

## सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया। 38 वर्षीय प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम %केजीएमयू% में डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया।

शुरुआती जांच में शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं सिविल अस्पताल

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनकी मौत किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से नहीं हुई।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई।पोस्टमार्टम के दौरान प्रतीक यादव के साले अमन बिष्ट मौजूद रहे। उनकी पत्नी और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पति के निधन की खबर मिलने के बाद दिल्ली से लखनऊ पहुंचीं। बताया गया कि वह हाल ही में सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए गई थीं और मंगलवार रात दिल्ली में रुकी थीं।अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अब विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते थे और जिम व रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, वह लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हाल ही में वह मुंबई से इलाज कराकर लौटे थे और तीन दिन पहले उन्हें मेदांता अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। उन्हें डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में रक्त जमने की शिकायत थी।

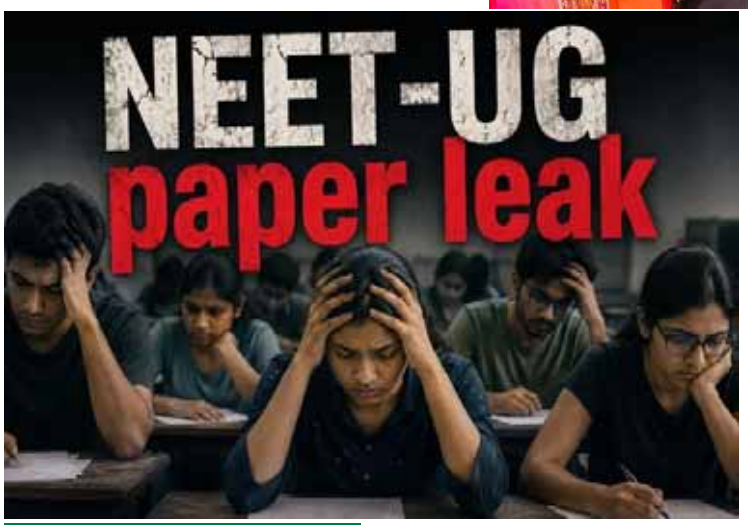


# पेपर लीक की परंपरा में आखिर कब लगेगी लगाम ?

## भारत में शिक्षा प्रणाली और शासन के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती बन गई है

राजेश कटियार /स्वराज इंडिया

कानपुर। पेपर लीक की परंपरा आखिर हमारे देश में कब समाप्त होगी यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यह परंपरा भारत में शिक्षा प्रणाली और शासन के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती बन गई है। 2024 और 2026 जैसे वर्षों में नीट और यूजीसी नेट जैसी प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा छीन लिया है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है कुछ परीक्षाओं को तो सरकार निरस्त कर देती है लेकिन कुछ में अयोग्य लोगों को सफलता मिल जाती है। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित नीट यूजी परीक्षा 2026 के पेपर लीक होने की घटना जितनी शर्मनाक है उससे अधिक यह दर्दनाक है।

शर्मनाक इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष नीट का पेपर लीक होता है फिर भी सड़ा हुआ सिस्टम इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कभी भी नहीं करवा पाता है और दर्दनाक इसलिए क्योंकि करीब 22 लाख से अधिक बच्चे परीक्षा निरस्त होने से मायूसी के शिकार हो गए हैं।

शिक्षाशास्त्री प्रवीण त्रिवेदी का कहना है कि नीट 2026 परीक्षा रद्द होने की घटना कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार सामने आ रही प्रशासनिक विफलताओं, पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और अव्यवस्थित निर्णयों की लंबी श्रृंखला का नया अध्याय है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर एनटीए का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? क्या देश में पारदर्शी, विश्वसनीय और वैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए या फिर हर साल लाखों छात्रों को अनिश्चितता, तनाव और अविश्वास की आग में झोंकने के लिए? एक आरोपी द्वारा कथित रूप से 10 लाख में पेपर खरीदने और 15 लाख में बेचने जैसी बातें यदि जांच में सही साबित होती हैं तो यह केवल नकल माफिया नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के समानांतर खड़े एक संगठित परीक्षा बाजार की तस्वीर है

लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह नहीं कि पेपर लीक हुआ। सबसे बड़ा दर्द यह है कि 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, मानसिक संतुलन और भविष्य को फिर से प्रयोगशाला बना दिया गया। वर्षों की तैयारी, सामाजिक दबाव, आर्थिक बोझ, कोचिंग संस्कृति की थकान और मानसिक अवसाद से गुजरते हुए छात्र परीक्षा देते हैं फिर अचानक शाम को खबर आती है परीक्षा रद्द। एनटीए की भूमिका पर सवाल इसलिए और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है। यूजीसी नेट 2024 रद्द हुई। नीट 2024 विवादों में रही। सीयूईटी लगातार तकनीकी और प्रबंधन गड़बड़ियों से घिरा रहा। हर बार एक नई समिति, नई जांच, नया आश्वासन लेकिन हर बार परिणाम वही व्यवस्था फिर असफल, आखिर एनटीए का गठन इसलिए किया गया था कि देश की परीक्षाओं को पेशेवर और सुरक्षित बनाया जाए या इसलिए कि हर साल करोड़ों छात्रों का भरोसा टूटता रहे? 2024 के विवादों के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डिजिटल कॉपी, एन्क्रिप्शन और सुरक्षा सुधारों की बातें हुई थीं। समितियाँ बनीं, विशेषज्ञ बुलाए गए,

बड़े-बड़े दावे किए गए लेकिन 2026 में फिर वही कहानी सामने है। इसका अर्थ साफ है या तो सुधार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहे या फिर संस्थागत इच्छाशक्ति ही कमजोर है। सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह है कि अब परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए अवसर से अधिक भय का प्रतीक बनने लगी है। छात्र पढ़ाई से ज्यादा यह सोचने लगे हैं कि परीक्षा होगी भी या नहीं? रिजल्ट रुकेगा तो नहीं? पेपर फिर लीक तो नहीं होगा? यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए शर्मनाक है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का पहला आधार भरोसा होता है। सच यह है कि यदि हर बड़े विवाद के बाद केवल सीबीआई जांच और उच्चस्तरीय समिति ही अंतिम प्रतिक्रिया बन जाए तो इसका मतलब है कि व्यवस्था समस्या को रोकने नहीं केवल उसके बाद बचाव करने में सक्षम रह गई है और जब किसी संस्था की पहचान लगातार गड़बड़ियों, लीक और अव्यवस्था से जुड़ने लगे, तो सवाल केवल अपराधियों पर नहीं उठते सवाल उस संस्था की क्षमता, जवाबदेही और अस्तित्व पर भी उठते हैं। अब यह मामला केवल नीट 2026 का नहीं रह गया।

यह भारत की परीक्षा प्रणाली और उसमें बैठे संस्थानों की विश्वसनीयता की परीक्षा है और दुर्भाग्य यह है कि इस परीक्षा में सबसे अधिक असफल वही तंत्र दिखाई दे रहा है जिसे निष्पक्षता का प्रहरी बनाकर खड़ा किया गया था।

# बदनीयती का विरोध करने पर महिला को मारी गोली, आरोपी हिरासत में

## » हमीरपुर के सुमेरपुर क्षेत्र में सुबह पशुओं को चारा डालने गई महिला पर हमला, ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी पकड़ा गया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

हमीरपुर। जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर गांव में बुधवार सुबह एक महिला को गोली मार दिए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने महिला के साथ बदनीयती करने की कोशिश की और विरोध करने पर तमंचे से फायर कर दिया।

जानकारी के अनुसार धुंधपुर गांव निवासी 37 वर्षीय सरस्वती, पत्नी कमल निषाद, बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे पशु बाड़े में जानवरों को चारा डालने गई थीं। इसी दौरान गांव का 56 वर्षीय अर्जुन वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने महिला को पकड़ने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने तमंचे से गोली चला दी।

गोली महिला के बाएं कंधे को चीरते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। घायल महिला ने बताया कि गोली चलाने के बाद आरोपी दोबारा तमंचा लोड करने लगा। इस बीच उन्होंने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया।महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी पास के एक कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सूचना मिलने पर सुमेरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया।घायल महिला को पहले सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस आरोपी को तमंचे सहित पकड़कर ले गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

# 400 करोड़ के जमीन घोटाले में पूर्व एडीएम समेत बैंक अफसरों पर एफआईआर

» थर्मल पावर प्लांट के नाम पर सरकारी जमीन गिरवी रख 1500 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप

» मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हुई कार्रवाई, भोगनीपुर के तहसीलदार ने दर्ज कराई एफआईआर

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर देहात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कानपुर देहात में करीब 400 करोड़ रुपये के बहुचर्चित जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर अधिग्रहीत सरकारी भूमि को अवैध तरीके से बैंकों में गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज लेने के मामले में पूर्व एडीएम, कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ थाना मूसानगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।**

तहसीलदार प्रिया सिंह की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ओ.के. सिंह, हिमावत पावर, लैन्को अनपरा पावर कंपनी तथा आईडीबीआई, कैनरा बैंक और पीएनबी के संबंधित अधिकारियों को नामजद किया गया है। मामले में जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में भोगनीपुर क्षेत्र के चपरघटा, कृपालपुर, भुण्डा, रसूलपुर और भरतौली समेत 7 गांवों की लगभग 2332 एकड़ भूमि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों को आवंटित की गई थी। शासन की शर्त थी कि 3 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर बिजली उत्पादन किया जाएगा, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी।आरोप है कि कंपनियों ने सरकारी एवं अधिग्रहीत भूमि को नियमों के विरुद्ध गिरवी रखकर बैंकों से लगभग 1500 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल कर लिया। न तो परियोजना शुरू हुई और न ही बैंक ऋण चुकाया गया। मामला तब खुला जब बैंकों द्वारा इस कीमती जमीन की नीलामी की तैयारी की जा रही थी।

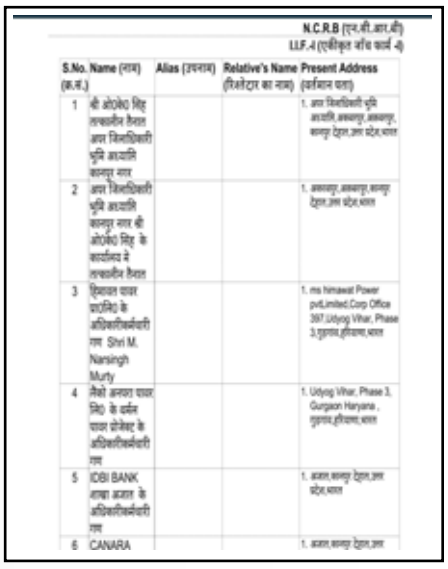

जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराई, जिसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई और जमीन को दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित दर्ज कराया गया।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है, जबकि बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासनिक और बैंकिंग महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों का कहना है कि जांच का दायरा और बढ़ सकता है तथा कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। योगी सरकार की इस कार्रवाई को प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन घोटालों पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है।



कपिल सिंह, जिलाधिकारी कानपुर देहात


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री ओ0के0 सिंह तत्कालीन तैनात अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर | | | 1. अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति,कानपुर,कानपुर, कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर श्री ओ0के0 सिंह के कार्यालय मे तत्कालीन तैनात | | | 1. कानपुर,कानपुर,कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 3 | हिमावत पावर प्रा0लि0 के अधिकारी/कर्मचारी गण Shri M. Narsingh Murty | | | 1. ms himawat Power pvt.limited Corp Office 397,Udyog Vihar, Phase 3,गुड़गांव,हरियाणा,भारत |
| 4 | मैसर्स अनपरा पावर लि0 के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारी/कर्मचारी गण | | | 1. Udyog Vihar, Phase 3, Gurgaon Haryana , गुड़गांव,हरियाणा,भारत |
| 5 | IDBI BANK शाखा [illegible] के अधिकारी/कर्मचारी गण | | | 1. [illegible],कानपुर देहात,उत्तर प्रदेश,भारत |
| 6 | CANARA | | | 1. [illegible],कानपुर देहात,उत्तर |

## परियोजना या जमीन का खेल?

थर्मल पावर प्लांट की परियोजना को विकास और रोजगार से जोड़कर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 15 वर्षों तक निर्माण शुरू न होना कई सवाल खड़े करता है। अब जांच में सामने आया है कि जमीन को वित्तीय लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। इससे सरकारी अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठे हैं।

## बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल

सरकारी और अधिग्रहीत भूमि को गिरवी रखने की अनुमति कैसे मिली, यह जांच का अहम बिंदु बन गया है। बैंक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। यदि नियमों की अनदेखी कर ऋण स्वीकृत हुआ है तो यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि बैंकिंग प्रणाली की जवाबदेही का भी गंभीर मामला बन सकता है।

## योगी सरकार का सख्त संदेश

प्रदेश सरकार इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और भू-माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी जमीनों की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज होना यह संकेत देता है कि अब पुराने मामलों की भी गहन जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

## कई और चेहरे आ सकते हैं सामने

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच अभी शुरुआती चरण में है। दस्तावेजों की पड़ताल में कई और अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी एजेंसियों की भूमिका सामने आने की संभावना जताई जा रही है। यदि वित्तीय लेनदेन और फाइल मूवमेंट की गहराई से जांच हुई तो यह मामला प्रदेश के बड़े जमीन घोटालों में शामिल हो सकता है।

# मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर गौरवान्वित हुईं ज्योति त्रिपाठी

## 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय परिवार ने दी शुभकामनाएं

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ/कानपुर देहात। राजधानी लखनऊ में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इुश्रद्ध स्नद्बह्ल4इुठुइुह्लद्ध द्वारा विभिन्न विभागों में चयनित हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, कानपुर देहात की श्रीमती ज्योति त्रिपाठी को स्टाफ नर्स (राजकीय सेवाएं) पद हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर चिकित्सालय परिवार में हर्ष का माहौल रहा। इस अवसर पर चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश कुमार आर्य सहित समस्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने श्रीमती ज्योति त्रिपाठी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

चिकित्सालय परिवार ने कहा कि यह उपलब्धि श्रीमती ज्योति त्रिपाठी के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सकों, पंचकर्म स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट एवं अन्य कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि वह अपने नए दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ करेंगी तथा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।मिशन रोजगार कार्यक्रम को युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए चिकित्सालय परिवार ने कहा कि इससे युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है।

# पेपर लीक की परंपरा पर आखिर कब लगेगी लगाम?

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। देश की शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक अब एक ऐसी गंभीर बीमारी बन चुकी है, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य, मेहनत और भरोसे को संकट में डाल दिया है। हर वर्ष किसी न किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आती हैं और उसके बाद शुरू होता है जांच समितियों, आश्वासनों और बयानबाजी का सिलसिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है आखिर इस परंपरा पर लगाम कब लगेगी?



साल 2024 और 2026 में नीट और यूजीसी नेट जैसी देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं पर लगे दाग ने यह साबित कर दिया कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी बेहद कमजोर है।

लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव के बीच तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने की एक खबर उनके सपनों को झकझोर देती है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश को झकझोर दिया। लगभग 22 लाख से अधिक छात्र असमंजस और मायूसी के माहौल में पहुंच गए। आरोप लगे कि प्रश्नपत्र लाखों रुपये में खरीदे और बेचे गए। यदि जांच में यह सच साबित होता है, तो यह केवल नकल माफिया का मामला नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के समानांतर चल रहे संगठित परीक्षा बाजार की भयावह तस्वीर है।

शिक्षाशास्त्री प्रवीण त्रिवेदी का कहना है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक विफलताओं, तकनीकी खामियों और कमजोर निगरानी व्यवस्था का परिणाम है। उनका सवाल बिल्कुल सीधा है आखिर एनटीए का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? क्या देश में पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए या हर वर्ष छात्रों को अनिश्चितता और अविश्वास के माहौल में धकेलने के लिए? वर्ष 2024 में भी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई थी। नीट लगातार विवादों में रही और सीयूईटी परीक्षा तकनीकी अव्यवस्थाओं से घिरी रही। हर बार नई जांच, नई समिति और नए दावे किए गए, लेकिन हालात नहीं बदले। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, एन्क्रिप्शन और डिजिटल सुरक्षा के बड़े-बड़े वादे किए गए, पर 2026 में फिर वही स्थिति सामने आ गई। इससे साफ है कि या तो सुधार केवल कागजों तक सीमित रहे या फिर व्यवस्था में इच्छाशक्ति की कमी है। अब यह मामला केवल नीट 2026 का नहीं रह गया है। यह भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। दुर्भाग्य यह है कि इस परीक्षा में सबसे अधिक असफल वही तंत्र दिखाई दे रहा है, जिसे निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रहरी बनाकर खड़ा किया गया था।

# सलामी के साथ बीएसएफ जवान

# दीपू यादव को दी गई अंतिम विदाई

## नम आंखों से ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि, भारत माता के जयकारों से गूंजा द्वारिकापुर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**कानपुर देहात। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में तैनात जवान दीपू यादव की मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान और सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। भोगनीपुर क्षेत्र के सट्टी थाना अंतर्गत द्वारिकापुर गांव निवासी 35 वर्षीय जवान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।**

जानकारी के अनुसार बीएसएफ जवान दीपू यादव छुट्टी पर अपने गांव द्वारिकापुर आए हुए थे। इसी दौरान गांव से कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए कानपुर के पनेशिया हॉस्पिटल ले गए, जहां करीब 20 दिनों तक उनका इलाज चला। उपचार के दौरान ही जवान ने दम तोड़ दिया।

मंगलवार को जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। लखनऊ से पहुंची सीमा सुरक्षा बल के जवानों की टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर को सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

अंतिम विदाई के समय पत्नी पुष्पा यादव, छह वर्षीय बेटी आराधना, पांच वर्षीय पुत्र रुद्र यादव तथा पिता मानसिंह यादव सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। जवान के पार्थिव शरीर को अग्नि दिए जाने के दौरान ÷भारत माता की जय÷ के नारों से पूरा गांव गूंज उठा और हर आंख नम दिखाई दी।

इस मौके पर अरुण यादव समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से बबलू राजा शेखपुर, प्रदीप यादव, रोहन भावी प्रधान शेखपुर, अंकित यादव, आनंद यादव, राकेश यादव, भोले, सुनील, प्रशांत, निशांत, मलखान यादव, राघवेंद्र यादव, अर्पित यादव, दीपू पाल, संदीप यादव, कालू यादव, अनूप यादव और कृष्णकांत यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

# समर कैंप का चौकी प्रभारी ने किया उद्घाटन, बच्चों की प्रतिभाओं को मिला मंच

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जूनियर विद्यालय सिठमरा में आयोजित समर कैंप का उद्घाटन सिठमरा चौकी प्रभारी अनूप कुमार पाण्डेय ने फीता काटकर किया। इस दौरान उनके साथ हमराही सुरेन्द्र कुमार और अनूप कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने पर जोर दिया गया।

चौकी प्रभारी अनूप कुमार पाण्डेय ने कहा कि समर कैंप बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रखकर उनकी नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता का विकास करते हैं। उन्होंने बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्कूल आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल 1090 और 112 पर संपर्क करें।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक शनेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि विद्यालय के बच्चों ने एक अंतरराष्ट्रीय, 3 राष्ट्रीय, 12 राज्य स्तरीय तथा 51 जिला स्तरीय पुरस्कार जीतकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि समर कैंप बच्चों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है, जिससे उनमें सामाजिक कौशल, आत्मनिर्भरता और नई कला सीखने की क्षमता विकसित होती है।

बहुभाषावाद उर्दू

सुलेख प्रतियोगिता में नूरे मुजस्सिन ने प्रथम, विशाल ने द्वितीय तथा नासिर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। समर कैंप में बच्चों को पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, कोडिंग और आउटडोर खेलों जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सहायक अध्यापक एवं राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नवीन कुमार दीक्षित ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को नई दिशा देते हैं और उनमें समूह में कार्य करने व निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं।

शिक्षिका माया देवी ने कहा कि उत्पादक गतिविधियां बच्चों को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखती हैं,

जबकि शिक्षिका गुंजन पाण्डेय ने समर कैंप को अच्छी आदतों के विकास का माध्यम बताया। अनुदेशक प्रियंका यादव ने कहा कि समर कैंप बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

# सभासद के प्रयासों से मुख्य मार्ग पर नाली क्रॉस निर्माण शुरू

## स्थानीय नागरिको को मिलेगी राहत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। अकबरपुर सदर बाजार पावर हाउस रोड स्थित अकबरपुर नयागंज में मदन गुप्ता के दरवाजे के सामने लंबे समय से जर्जर पड़े नाली क्रॉस का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू हो गया। इस निर्माण कार्य के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल है।यह मार्ग अकबरपुर नगर का प्रमुख और व्यस्त मार्ग माना जाता है, जहां नाली क्रॉस क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। गंदा पानी सड़क पर भर जाने से राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बरसात और जलभराव के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी।

स्थानीय लोगों के अनुसार नाले के पास धर्मशाला और प्राचीन गौरी शंकर महादेव मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। गंदगी और कीचड़ के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

क्षेत्रीय वार्ड सभासद निर्लेप भारती एवं नामित सभासद जय कुमार उर्फ बबलू भारती ने नगर निकाय की बैठकों में लगातार इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। काफी प्रयास और जद्दोजहद के बाद आखिरकार नाली क्रॉस निर्माण कार्य शुरू कराया गया।

सभासदों ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को जाम, जलभराव और कीचड़ से राहत मिलेगी तथा मुख्य मार्ग पर आवागमन सुगम हो सकेगा। क्षेत्रवासियों ने भी निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताते हुए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

# कैश वैन लूटकांड के दो इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

## 20 मिनट चली ताबड़तोड़ फायरिंग, एक लाख के इनामी समीर और जुबैर मारे गए

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

**गाजियाबाद। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में कैश वैन लूटकांड के दो इनामी बदमाश मारे गए। मुठभेड़ करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें दोनों ओर से 15 से अधिक राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक लाख रुपये के इनामी समीर और जुबैर ढेर हो गए, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार कॉम्बिंग अभियान चला रही है।**

आरोपी समीर

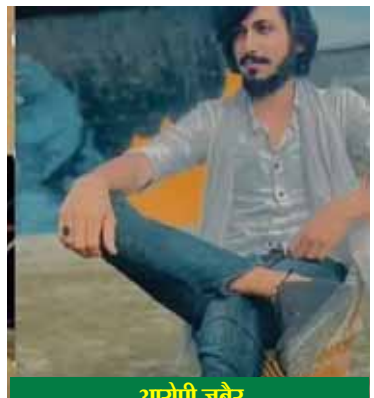
आरोपी जुबैर

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कैश वैन लूटकांड में शामिल बदमाश वेव सिटी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार दिखाई दी। पुलिस द्वारा कार रोकने का प्रयास करते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई गोलीबारी में एक सब इंस्पेक्टर और दो कॉन्स्टेबल घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में समीर और जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक समीर को दो गोलियां लगीं, जबकि जुबैर के सीने में गोली लगी थी।पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से 9 लाख 10 हजार रुपये नकद, दो पिस्टल, दो तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद की गई है। दोनों आरोपी विजयनगर क्षेत्र के निवासी थे और लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे। जांच में सामने आया कि 6 मई को छह बदमाशों ने कैश वैन चालक को बंधक बनाकर 27 लाख रुपये लूट लिए थे। वारदात के बाद आरोपी कैश वैन को मसूरी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे किनारे छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार लूटकांड का मास्टरमाइंड जुबैर था, जिसने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को गैंग में शामिल कर पूरी साजिश रची थी।

# मेरठ में मारा गया एक लाख का इनामी जुबैर एसटीएफ-पुलिस की जॉइंट कार्रवाई

**अलीगढ़ में एएमयू शिक्षक हत्याकांड के बाद से फरार था शार्प शूटर**

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ और मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार देर रात एक लाख रुपये का इनामी बदमाश जुबैर मुठभेड़ में मारा गया। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड स्थित अलीपुर इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। मारा गया जुबैर अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के नौशा गांव का रहने वाला था और लंबे समय से हत्या, लूट और डकैती जैसी वारदातों में वांछित चल रहा था।

पुलिस के अनुसार जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय शार्प शूटर था।उस पर अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र में 24 दिसंबर 2025 को एएमयू शिक्षक राव दानिश की हत्या करने का आरोप था। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वारदात के बाद से वह फरार चल रहा था और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छिपकर रह रहा था।

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि जुबैर मेरठ के हापुड़ रोड इलाके में किसी साथी से मिलने आने वाला है। इसके बाद एसटीएफ की मेरठ यूनिट और स्थानीय पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख जुबैर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई।मुठभेड़ के दौरान जुबैर को तीन गोलियां लगीं। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि मौके से दो पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे के साथ एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब दो दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज थे।

**रैपिड रेल से बदलेगी यूपी की रफ्तार**

# लखनऊ-प्रयागराज अब सिर्फ 48 मिनट हुआ दूर

## दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को भी मिली रफ्तार, अयोध्या तक सफर भी होगा बेहद आसान

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाली दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर के शुरू होने के बाद प्रदेश के बड़े शहरों के बीच यात्रा का समय रिकॉर्ड स्तर तक घट जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार लखनऊ से प्रयागराज का सफर अब महज 48 मिनट में पूरा हो सकेगा, जबकि वर्तमान में इस दूरी को तय करने में तीन से पांच घंटे तक लग जाते हैं।

परियोजना के तहत दिल्ली से लखनऊ की दूरी केवल 2 घंटे 12 मिनट में पूरी होगी। वहीं धार्मिक नगरी अयोध्या तक पहुंचना भी पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। लखनऊ से अयोध्या की यात्रा लगभग 35 मिनट में पूरी होने का अनुमान है। इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर प्रयागराज में तकनीकी सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन का ट्रैक प्रयागराज जंक्शन के ऊपर से निकाला जाए या शहर के बाहरी हिस्से से। विशेषज्ञों का मानना है कि फाफामऊ और भदोही के रास्ते कॉरिडोर ले जाना ज्यादा व्यावहारिक रहेगा, क्योंकि शहर के भीतर जमीन अधिग्रहण और घनी आबादी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना केवल यात्रा को तेज नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगी। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

### भारत में पहली रैपिड रेल कहां शुरू हुई?

देश की पहली रैपिड रेल सेवा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर शुरू की गई थी। इसे नमो भारत ट्रेन के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का पहला चरण अक्टूबर 2023 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक शुरू हुआ था। हाईस्पीड, आधुनिक सुविधाओं और कम यात्रा समय के कारण यह परियोजना देश के शहरी परिवहन मॉडल में बड़ी क्रांति मानी जा रही है।

# ‘समाजसेवा’ की आड़ में जमीन का खेल?

स्वराज इंडिया एक्सक्लूसिव

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

## जिस जमीन में शिकायतकर्ता की खुद तय था 30 प्रतिशत हिस्सा, उसी पर शिकायत कर चला बुलडोज़र!

अयोध्या। अयोध्या के रामजानकी मंदिर दिल्ली दरवाजा से जुड़ी जमीनों पर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई बुलडोज़र कार्रवाई अब बड़े विवाद और सवालों के घेरे में आ गई है। गाटा संख्या 52, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 80, 81 और 89 पर हुई कार्रवाई के बाद अब ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो पूरे घटनाक्रम की अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता संजय यादव पुत्र नन्द किशोर यादव ने 28 जनवरी 2016 को एक नोटरी सुलहनामा किया था। इस दस्तावेज में साफ उल्लेख है कि जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर उनके द्वारा किए गए मुकदमे और आपत्तियां वापस ली जाएंगी तथा दोनों पक्ष 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत लाभांश के आधार पर साथ मिलकर व्यापार करेंगे। यानी जिस जमीन को लेकर आज अवैध कब्जे और मंदिर की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी जमीन के सौदे में शिकायतकर्ता खुद हिस्सेदार था।

इतना ही नहीं, इससे एक वर्ष पूर्व जनता दरबार में की गई शिकायत पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी राम सहाय यादव ने 28 फरवरी 2015 को अपने पत्रांक 328/एसटीएस/जनता दरबार/दिल्ली दरवाजा की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि उक्त भूमि रामजानकी खेवटदारी मातहती की जमीन है, जिसकी सुरक्षा और देखरेख का सम्पूर्ण दायित्व सरवराकार कु. निर्मला रावत आदि का है तथा शिकायतकर्ता को उसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि पुलिस बल के माध्यम से हस्तक्षेप रोका गया।

इसके बाद थाना कैंट में आईजीआरएस शिकायत पर तत्कालीन एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने 18 अक्टूबर 2018 को एसएसपी को भेजी अपनी आख्या में लिखा कि शिकायतों से परेशान होकर सरवराकार कु. निर्मला रावत ने शिकायतकर्ता को 8 बिस्वा जमीन दान स्वरूप दे दी थी, जहां वह गिट्टी-मोरंग की दुकान संचालित करता है। रिपोर्ट के अनुसार बाद में उसने दुकान विस्तार के लिए डेढ़ बिस्वा अतिरिक्त जमीन मांगी, जो न मिलने पर लगातार शिकायतें, अखबारों में प्रकाशन और नए विवाद खड़े किए जाने लगे। इतना ही नहीं, इस प्रकरण में दायर प्रकीर्ण वाद भी 17 अप्रैल 2023 को अपर जिला जज न्यायालय से खारिज हो चुका है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या आईजीआरएस शिकायतों और मीडिया प्रकाशनों के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों को अधूरी जानकारी देकर गुमराह किया गया?

क्या बुलडोज़र कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता की भूमिका और पुराने दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हुई? स्थानीय लोगों का आरोप है कि फर्जी शिकायतों के जरिए दबाव और धन उगाही का खेल खेला गया। पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं इस संबंध में शिकायतकर्ता पक्ष से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

# कृषि विश्वविद्यालय में संबद्धीकरण का हुआ बड़ा खेल!

## मूल कॉलेजों से गायब शिक्षक, विश्वविद्यालय मुख्यालय में वर्षों से जमे अफसर और वैज्ञानिक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संबद्धीकरण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि कृषि महाविद्यालयों और कृषि ज्ञान केंद्रों के लिए नियुक्त शिक्षक एवं वैज्ञानिक वर्षों से विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमे हुए हैं, जिससे कृषि शिक्षा और प्रसार कार्य प्रभावित हो रहा है।जानकारी के अनुसार कई शिक्षक अपने मूल तैनाती महाविद्यालयों से वेतन आहरित कर रहे हैं, लेकिन अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय मुख्यालय में संबद्ध होकर कर रहे हैं। आजमगढ़ के कोटवा कृषि महाविद्यालय सहित कई संस्थानों में सैकड़ों छात्र-छात्राओं की पढ़ाई सीमित शिक्षकों के सहारे चल रही है।

वहीं संबद्ध शिक्षक विश्वविद्यालय में प्रभावशाली पदों पर बने हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि कृषि ज्ञान केंद्रों के कई कर्मचारी वर्षों से अपने कार्यस्थलों पर नहीं गए और विश्वविद्यालय में ही तैनात हैं। आरोप यह भी है कि वरिष्ठता की अनदेखी कर जूनियर शिक्षकों को विभागाध्यक्ष और अधिष्ठाता जैसे पद दिए गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं तो संबद्धीकरण का खेल आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है।

# अज्ञात युवक ने तीन गाड़ियों में लगाई आग

## » मोटरसाइकिल जलकर राख, स्कूटी और कार भी चपेट में आईं

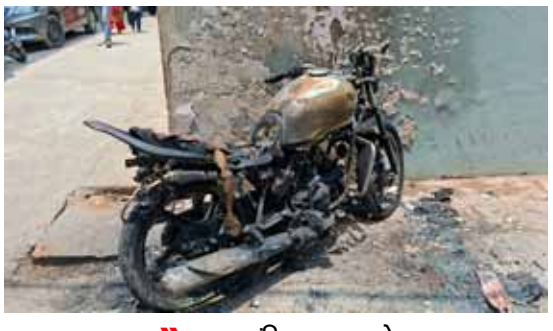

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के दीलकुशा कॉलोनी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध युवक ने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। घटना धारा रोड स्थित कॉलोनी के पास की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि पास में खड़ी स्कूटी और कार भी आग की चपेट में आने से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक आग लगाने वाले संदिग्ध युवक की शिनाख्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वह नशे का आदी है। फिलहाल सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के निर्देशन में नगर कोतवाली क्षेत्र पुलिस कई अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस ने मोटरसाइकिल मालिक से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

# साइबर ठगों पर अयोध्या पुलिस का डिजिटल प्रहार!

फोटो प्रतिकात्मक

## » गलत ट्रांजेक्शन से फंसे 74 हजार रुपये वापस, साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में जहां साइबर अपराधी मोबाइल और लिंक के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं,

वहीं साइबर क्राइम थाना अयोध्या ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई कर पीड़िता को राहत दिलाई है।

एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायत के अनुसार एक महिला के खाते से गलती से 74 हजार रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए थे। मामला सामने आते ही साइबर थाना सक्रिय हुआ और तकनीकी जांच के जरिए पूरी धनराशि वापस करा दी गई।

इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक मो. अरशद, कांस्टेबल हरिवीर सिंह और महिला कांस्टेबल रोली सिंह की टीम ने अहम भूमिका निभाई। अक्सर पुलिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन इस कार्रवाई ने साबित किया कि अगर तकनीक और इच्छाशक्ति साथ हो तो साइबर ठगों का खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता।

अयोध्या पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक और कॉल से सतर्क रहें, क्योंकि एक क्लिक आपकी पूरी जमा-पूंजी साफ कर सकता है।

## अफगान सीमा से सटे लक्की मरवत में आत्मघाती हमला

# खैबर पख्तूनख्वा फिर दहला: बाजार में रिक्शा बम विस्फोट, 9 की मौत, 35 घायल

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

नई दिल्ली। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवाद ने एक बार फिर खूनी वार किया है। अफगानिस्तान सीमा से सटे लक्की मरवत जिले के एक व्यस्त बाजार में हुए भीषण आत्मघाती बम विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बाजार की कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और आसपास खड़े वाहन जलकर खाक हो गए। धमाके के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विस्फोटकों से भरे एक रिक्शे को बाजार के बीच में उड़ा दिया गया। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक महिला भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया। पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते और खुफिया एजेंसियां विस्फोट के तरीके और इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच में जुट गई हैं।

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही बन्नू जिले में सुरक्षा चौकी पर हुए आत्मघाती हमले और गोलीबारी में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। उस हमले के लिए पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को जिम्मेदार ठहराया था। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि लक्की मरवत हमला भी उसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। लगातार बढ़ते आतंकी हमलों ने पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस्लामाबाद ने हाल ही में अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर सीमा पार से संचालित आतंकी गतिविधियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सीमा के पास सक्रिय आतंकी गुट उसके सुरक्षा ढांचे को लगातार निशाना बना रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पाकिस्तान-अफगान सीमा क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों, पुलिस चौकियों और भीड़भाड़ वाले बाजारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना नेतृत्व ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

➪ पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

### टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों में फिर सक्रिय हुआ है। संगठन पुलिस, सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार टीटीपी अब छोटे-छोटे मॉड्यूल के जरिए हमले कर रहा है, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है।

### हाल के बड़े आतंकी हमले

| तारीख | स्थान | घटना | मृतक |
|---|---|---|---|
| 13 मई 2026 | लक्की मरवत, खैबर पख्तूनख्वा | बाजार में रिक्शा बम विस्फोट | 9 |
| 08 मई 2026 | बन्नू जिला | सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती हमला व गोलीबारी | 15 पुलिसकर्मी |
| 28 अप्रैल 2026 | पेशावर | पुलिस वाहन को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट | 6 |
| 17 अप्रैल 2026 | क्वेटा, बलूचिस्तान | सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला | 8 |
| 02 अप्रैल 2026 | उत्तरी वजीरिस्तान | सैन्य चौकी पर फिदायीन हमला | 10 सैनिक |

### क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी हमले?

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद पाकिस्तान-अफगान सीमा क्षेत्र में आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ी हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी जैसे संगठन सीमा पार सुरक्षित ठिकानों से हमलों की साजिश रच रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में कमजोर निगरानी और स्थानीय नेटवर्क भी आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं।

### पाकिस्तान-अफगान रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव

लगातार आतंकी घटनाओं के बाद इस्लामाबाद और काबुल के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान पहले भी अफगान सरकार पर आतंकियों को शरण देने के आरोप लगा चुका है। यदि हमले जारी रहे तो सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

### बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके क्यों निशाने पर?

आतंकी संगठन ज्यादा दहशत फैलाने के लिए भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को चुनते हैं। ऐसे हमलों का मकसद केवल जनहानि नहीं बल्कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करना भी होता है। इससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है।

## ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम से नक्शा पास कराने, टैक्स जमा करने और वित्तीय लेन-देन की सुविधा मिलेगी

# यूपी में डिजिटल क्रांति: अब घर बैठे पास होगा मकान-दुकान का नक्शा

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायतों की सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और टैक्स सहित सभी शुल्क डिजिटल माध्यम से जमा कर पाएंगे।

सरकार द्वारा लागू किए जा रहे ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) के तहत नक्शा स्वीकृति, टैक्स भुगतान, नोटिस जारी करने, आरसी काटने और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं को पोर्टल से जोड़ा जाएगा। विभाग ने सभी जिला पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में अधिकतर प्रशासनिक और वित्तीय कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित किए जाएं।

बताया जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर जल्द ही इस नई डिजिटल सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था लागू करना है, जैसी शहरी विकास प्राधिकरणों में लागू है। इसके तहत पूरे प्रदेश में बिल्डिंग बाई लॉज के एक समान नियम लागू होंगे, जिससे अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त होंगी।

नई प्रणाली लागू होने से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक नक्शा पास कराने और टैक्स जमा करने के लिए लोगों को कई स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करना पड़ता था, जिससे देरी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने के बाद आवेदन की निगरानी ऑनलाइन होगी और हर चरण का रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से जिला पंचायतों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। टैक्स वसूली अधिक पारदर्शी होने से राजस्व संग्रह बेहतर होगा और पंचायतें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम ग्रामीण प्रशासन में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

### भ्रष्टाचार पर असरदार प्रहार

ऑफलाइन प्रक्रिया में फाइलों के लंबित रहने और अवैध वसूली की शिकायतें आम थीं। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद मानव हस्तक्षेप कम होगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नियंत्रण संभव होगा।

### ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को मजबूती

सरकार का यह कदम ग्रामीण प्रशासन में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा। अब तक शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति की सुविधा थी, लेकिन ग्रामीण जनता इससे वंचित थी। नई व्यवस्था से गांवों में भी तकनीकी आधारित पारदर्शी प्रशासन की शुरुआत होगी।

### पंचायतों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

डिजिटल टैक्स कलेक्शन से राजस्व रिसाव कम होगा और वसूली में पारदर्शिता आएगी। इससे जिला पंचायतों की आय बढ़ सकती है। सरकार को उम्मीद है कि पंचायतें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी और विकास कार्यों के लिए संसाधन बेहतर तरीके से जुटा सकेंगी।

- अब घर बैठे ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा मिलेगी।
- टैक्स और अन्य शुल्क डिजिटल माध्यम से जमा होंगे।
- नोटिस, आरसी और वित्तीय लेन-देन पोर्टल से संचालित होंगे।
- पूरे प्रदेश में बिल्डिंग बाई लॉज के समान नियम लागू होंगे।
- जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
- डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार और देरी पर अंकुश लगेगा।
- ऑनलाइन सिस्टम से जिला पंचायतों की आय बढ़ने की उम्मीद।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com